Media/LKO/0023

हिन्दुस्तान लखनऊ •गुरुवार •11 दिसम्बर 2014 10

प्रवेशकर से छूट का अब तक शासनादेश नहीं

राज्य मुख्यालय | संतोष वाल्मीकि

उत्तर प्रदेश सरकार ने बीती 12 नवम्बर को अपनी कैबिनेट बैठक में प्रवेश कर से चीनी मिलों को छूट दिए जाने के फैसले पर मुहर लगा दी लेकिन इसके बावजूद शासनादेश जारी नहीं हो सका। नतीजतन, यूपी की चीनी मिलें अपनी चीनी बेच ही नहीं पा रही हैं बगैर प्रवेश कर के चीनी बेचने पर वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी ऐतराज कर रहे हैं।

महाराष्ट्र और कर्नाटक चालू पेराई सत्र में अपनी चीनी 2400 से 2600 रुपए प्रति कुन्तल के भाव उत्तर भारत के बाजार में धड़ल्ले से बेच रहे हैं। उधर, उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों की लागत ही 3400 रूपए प्रति कुन्तल से ऊपर आ रही है। ऐसे में यूपी की मिलों की चीनी बाजार में खप ही नहीं पा रही है। इस दिक्कत के बीच यूपी शुगर मिल्स एसोसिएशन ने केन्द्र से गुहार लगाई है। उसकी मांग है कि केन्द्र तत्काल चीनी का आयात रोके और निर्यात शुरू करे। एसोसिएशन के सचिव दीपक गुप्तारा की ओर से हाल में केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखा गया है।

चीनी मिलें परेशान

- बगैर प्रवेश कर मिलों को चीनी बेचने से रोक रहा वाणिज्य कर विभाग
- महाराष्ट्र व कर्नाटक की सस्ती चीनी से यूपी के मिल मालिक परेशान